



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—बांध 3—चा. चा. (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 6, 1992 अग्रहायण 15 1914

No. 496] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 6, 1992/AGRAHAYANA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अधिक सुरक्षित के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

मुह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1992

सं. क्र. वि. 912(म) —राष्ट्रपति द्वारा जारी की
महानिम्नलिखित उद्घोषणा संबंधारण के सूचनाएँ प्रका-
षित की जा रही हैं—

थंडे में, भारत के राष्ट्रपति, शकर वयाल शमी का
संभिधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है
जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का शासन भारत के संविधान
(जिसके द्वारा हमें पश्चात् “संविधान” कहा गया है) के
उत्तरध्रुवी के अन्तर्गत नहीं फलस्थानी जा सकता है,

अधिकारी भवन में, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त
अधिसूचित की तरफ उत्तरप्रदेश में सभी बैठाने वाली अन्य

सभी शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता
है, कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कानूनों और उत्तर
राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके
द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्र-
पति के रूप में स्वयं संभालता हूँ;

(ख) ओरिजन करता हूँ कि उक्त राज्य के विधानमंडल
की शक्तियाँ सदृढ़ द्वारा या उसको प्राधिकार के धर्मीय
प्रयोक्तव्य होगी, और

(ग) तिम्तिमिक आनुषष्ठिक और पारिणामिक उप-
बन्ध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों
का प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या
आठनीपुर्ण प्रतीत होते हैं, अर्थात्—

(द) इस उद्घोषणा के उन्नयन विध (क) के
आधार पर मेरे द्वारा सभाले गए कृत्यों और
उत्तरी 15वीं शक्तियों को प्रयोग करते हैं, मेरे लिए भारत
भूमिका

के राष्ट्रपति के स्वर्ग में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझ उक्त राज्य के राज्यपाल के भावधन से कार्य करना विविध होगा;

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपर्योगों के प्रतिवेदन को एवंदारा निलंबित किया जाता है; अर्थात्:—

अनुच्छेद 3 के परन्तु का उत्तरा भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल को निर्देश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उत्तरा भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महानेतावरीज्ञक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रदत्त किए गए प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 का खंड (3) का उत्तरा भाग जितने का संबंध मंत्रियों द्वारा राज्य सरकार के कार्य के आवंटन से है;

अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उत्तरा भाग जितने का संबंध राज्य को विधान सभा द्वारा संकलन को पारित करने से है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1), और खंड (2) का उपखंड (क); अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 179 के खंड (ख) और (ग) और उस प्रावृद्धि का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 180, 181 और 182; अनुच्छेद 183 का खंड (ग) और उसका परन्तुक;

अनुच्छेद 185;

अनुच्छेद 186 का उत्तरा भाग जितने का संबंध विधान सभा के बेतरों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 187 के खंड (3) का उत्तरा भाग जितने का संबंध विधान सभा के ग्राहक के साथ परामर्श से है;

अनुच्छेद 188 का उत्तरा भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्य से है;

अनुच्छेद 189, 193 और 194;

अनुच्छेद 193 का उत्तरा भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्यों के बेतरों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 199 के खंड (3) और (4);

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उत्तरा भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के बेतरों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उत्तरा भाग जितने का संबंध शासन सहित इरोड़ के राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) उक्त राज्य को विधान सभा एवंदारा भाग की जाती है;

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निरेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधानमंडल या उसके सदरों ने प्रति किसी निवेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके फूर्झों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अनुचित न हो, संदर्भ के प्रति निवेश लगाया जाएगा और विधिव्यवस्था अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल या उसके सदरों के प्रति निवेश का अर्थ अन्यथा राष्ट्रपति और संदर्भ या उसके सदरों के प्रति निवेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें को कोई वान अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं); अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुच्छेद 51 रा 1 से ले तरने 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपर्योगों पर प्रभाव नहीं लालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (1) के प्रधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समसे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(v) संविधान में राज्य के विधानमंडल के द्वारा उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों वह उन अधिनियमों और विधियों को समाविष्ट करता है औ इस उत्थोषणा के आवार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के

खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रथा प्रधिकारों द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग फरते हुए बनाए गए हैं और संयुक्त प्रान्त सामान्य खंड 'प्रधिनियम 1904 (1904 का यू.पी. प्रधिनियम' 1) और सामान्य खंड प्रधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उन्ना मात्र जिसना राज्य की विधियों पर लाए हैं ऐसे किसी प्रधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी दृष्टि भानों यह उप राज्य के विधान मंडल का प्रधिनियम हो)।

नई दिल्ली,

दिनांक : ८ दिसम्बर, 1992

शंकर दयाल शर्मा

राष्ट्रपति

[फा. सं. 5/11013/17/92-सी.एम.प्रार.]

माधव गोडबोले, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1992

G.S.P. 912(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :—

Whereas, I Shunker Dayal Sharma, President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Uttar Pradesh cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
 - (i) In the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

articles 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto; article 185;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

so much of clause (3) of article 187 as relates to consultation with the Speaker of the Legislative Assembly;

so much of article 188 as relates to a member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive); clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House; thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provision of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State,

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

SHANKER DAYAL SHARMA

PRESIDENT

New Delhi
Dated December 6, 1992

प्रादेश

नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 1992

सा.का.नि 913(प्र)।—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया लिम्लिकित प्रादेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किए गए रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा प्रायः दिसंबर के छठवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के छठ (ग) के उपचाँड (1) का अनुवरण करते हुए, मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रचलित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनकी राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के छठ (क) ने आप्तवार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति वे शक्तियाँ, निर्देशन और नियंत्रण के अध्यवेदन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,

दिसंबर 6 दिसंबर 1992

शकर दयाल शर्मा

राष्ट्रपति

[मा. सं 5/11013/17/92-सी एस आर]

मानव गोदानपत्र, नई संविधा

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1992

G.S.R. 913(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (g) of the Proclamation issued on this the 6th day of December 1992 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (g) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

SHANKER DAYAL SHARMA

New Delhi

PRESIDENT

Dated December 6, 1992.

[F. No. V/11013/17/92-CSR]

[F. No. V/11013/17/92-CSR]

MADHAV GODBOLE, Home Secretary

MADHAV GODBOLE, Home Secretary